भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3252
दिनांक 12 मार्च, 2026

बुर्किना फासो के साथ प्रस्तावित तेल समझौता

†3252. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने बुर्किना फासो के साथ लगभग पंद्रह बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के तेल संसाधनों के आयात अथवा विकास के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो, इसकी प्रकृति, अवधि, वित्तीय प्रतिबद्धताएं और शामिल भारतीय सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की संस्थाओं सहित समझौते का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतर-सरकारी समझौता ज्ञापन अथवा वाणिज्यिक अनुबंध किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे सौदे की आर्थिक व्यवहार्यता, भू-राजनीतिक निहितार्थों और ऊर्जा सुरक्षा लाभों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारत के कच्चे तेल के स्रोत में विविधता लाने और दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) नहीं।

(ड.) कच्चे तेल की आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी एक क्षेत्र से कच्चे तेल पर निर्भरता के जोखिम को कम करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उद्यम (पीएसईज), जो बोर्ड द्वारा संचालित कंपनियां हैं, अपनी तकनीकी और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न स्रोतों से कच्चा तेल प्राप्त करते हैं। वर्तमान में, ये पीएसईज मिडिल ईस्ट में इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला, कनाडा, कोलंबिया, ब्राजील और मैक्सिको जैसे नए आपूर्तिकर्ताओं सहित 41 देशों से कच्चे तेल का आयात करती हैं।

*****